

इंदौर, भोपाल
व रायपुर से एक
साथ प्रकाशित

दैनिक

आदित्य भारत

सदैव सत्य के साथ...

इंदौर
गुरुवार,
27 मार्च,
2025

मुख्यमंत्री का भोपाल उत्सव मेला समिति ने जीआईएस की सफलता के लिए किया सम्मान

हम विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं : सीएम यादव

संवाददाता • भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश के चहुंमुखी विकास में मध्यप्रदेश का योगदान अद्वयल रहेगा। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 5 साल में हम प्रदेश का

संबोधन

सालाना बजट योगुना कर देंगे। कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे बल्कि नागरिकों की आय बढ़ाकर अपने बजट को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल की प्राकृतिक सम्पदा और इसके पुरा-इतिहास के संवर्धन में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें जनता की सेवा का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा आयोजित नागरिक सम्मान समारोह को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम भोपाल को एक सुंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे। भोपाल शहर में सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों में नगर द्वार बनाए जाएंगे। भोजपुर मंदिर रोड पर 'भोज द्वार' और इंदौर-उज्जैन मार्ग पर विक्रमादित्य के सुशासन के प्रतीक स्वरूप 'विक्रम द्वार' बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस में विश्व



से उद्योगपति भोपाल आए। भोपाल आकर उन सभी को आनंद आ गया, क्योंकि यहां की झीलें, तालाब और यहां की संस्कृति जीवंत हैं, यही हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा कि

भोपाल देश का एकमात्र राजधानी क्षेत्र है जहाँ मानव और बाघों के सह-अस्तित्व का अनोखा और अद्वितीय उदाहरण विद्यमान है। भोपाल शहर के समीप ही रातापानी अभयारण्य

है। यहां दुर्लभ बाज मिलने की भी पुष्टि हुई है। यह हमारी राजधानी को और भी आकर्षक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भोपाल शहर का सतत सौन्दर्यकरण कर रहे हैं। हम

भोपाल की विरासतों को चिरस्थायी बनाए रखेंगे।

भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सम्मान किया गया। भोपाल के 35 से अधिक व्यापारी संघों, उद्योगपतियों एवं समाजसेवियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का होली मिलन समारोह में आत्मीय सम्मान कर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति (जीआईएस) आयोजित करने और अपनी कुशलता व कर्मठता से जीआईएस को सफल बनाने के लिए भोपाल मेला उत्सव समिति द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रशस्ति (सम्मान) पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सबके सहयोग से हमको विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तक जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री रघुनंदन शर्मा, नगर निगम के सभापति श्री किशन सुर्यवंशी, श्री रवीन्द्र यति, भोपाल मेला उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल, डीबी ग्रुप के चेयरमैन श्री सुधीर अग्रवाल, श्री संदीप अग्रवाल, श्री संचय अग्रवाल, श्री राहुल कोठारी, श्री आशीष अग्रवाल सहित भोपाल शहर के सभी व्यापारी संघों के पदाधिकारी, उद्योगपति एवं समाजसेवी उपस्थित थे। मेला समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि जीआईएस ने पूरे विश्व में भोपाल की शान बढ़ाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिली है।

न्यूज ब्रीफ

मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर संसद में बोलने का अवसर न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैं जब भी लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता हूँ, तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। मैं एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन से बोलने नहीं दिया गया।

टी-सीरीज के नोटिस पर भड़क गए कुणाल कामरा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित मजाक के बाद विवादों में आए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने अब म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज पर अपनी भड़कावट निकाली है। कामरा ने बुधवार को दावा किया कि टी-सीरीज ने उनके वीडियो के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। उनके पैरोडी के एक वीडियो को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए YouTube द्वारा फ्लैग किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम जाएंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम स्थित रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी नए पंवन ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। नया पंवन ब्रिज 1914 में बने पुराने ब्रिज की जगह होगा, जिसे जंग की समस्या के कारण 2022 में बंद कर दिया गया था।

महादेव सट्टा एप मामला

भूपेश बघेल सहित नेताओं, अफसरों के ठिकानों पर छापे

संवाददाता • रायपुर

सीबीआई ने बुधवार को कथित 6 हजार करोड़ रुपए के महादेव सट्टा एप मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई समेत 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित पटुमनगर आवास और रायपुर स्थित सरकारी बंगले पर दबिश दी है। वहीं उनके राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा, उनके दो ओएसडी, उनकी उप सचिव रही सोनिया चौरसिया, भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव के सेक्टर पांच

छापा

स्थित आवास, भिलाई में केपीएस स्कूल के संचालक निशांत त्रिपाठी, चार आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस ऑफिसर्स के घर छापेमारी की गई है।

सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंधोरे के निवास पर भी छापे मारा है। जिन आईपीएस के घर रेड हुई है, उनमें पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, रायपुर के पूर्व एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव शामिल हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और संजय ध्रुव के साथ टीआई गिरीश तिवारी के घर भी दबिश दी गई है। वहीं केपीएस स्कूल के संचालक निशांत त्रिपाठी, हवलदार संदीप दीक्षित और राधाकांत पांडेय के अलावा इसी मामले में गिरफ्तार तीनों भाई क्रमशः पुलिस आरक्षक भीम यादव, सहदेव यादव और अर्जुन यादव के घर पर भी सीबीआई ने छापे मारा है।



राज्य सरकार का यह कहना

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि «ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है राजनीतिक आधार पर कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं उनकी जांच सीबीआई-ईडी लगातार कर रही है।» वहीं, डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्हें सीबीआई और ईडी पर विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने खुद सदन में कहा था कि कुछ विषयों पर सीबीआई जांच की जरूरत है।

छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली सहित 60 जगह दबिश

महादेव एप सट्टेबाजी घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई ने छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली सहित 60 जगहों पर छापेमारी की है। अकेले दुर्ग जिले में ही 16 जगह दबिश दी गई है, जिसमें राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और महादेव बुक के प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े परिसर शामिल हैं। इससे पहले ईडी की टीम ने 10 मार्च को भूपेश बघेल के भिलाई स्थित पटुमनगर आवास पर और उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुल 14 ठिकानों ईडी की टीम ने दबिश दी थी।

नेताओं की प्रतिक्रिया...

कांग्रेस ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "अब सीबीआई आई है। बघेल ने कहा है कि सीबीआई ने कांग्रेस की बैठक के लिए उनके नयी दिल्ली जाने से पहले उनके आवास पर छापेमारी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, "तमाम असफल छापों और नाकाम साजिशों के बाद, अब भाजपा ने सीबीआई को भूपेश बघेल और देवेन्द्र यादव के पीछे लगा दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्रवाई की निंदा की और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बघेल को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार शाखा के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, "जब से बघेल पंजाब के पार्टी प्रभारी बने हैं, तब से भाजपा डरी हुई है।

राणा सांगा विवाद

करणी सेना ने की तोड़फोड़, पथराव में पुलिसकर्मी घायल



एजेंसी • आगरा

राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना घेराव करने पहुंची थी। यहां पर पहले ही पुलिस तैनात थी। करणी सेना के कार्यकर्ता

नारेबाजी करते हुए आवास से प्रवेश करने लगे। इस दौरान

हमला

पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया, तो वे उग्र हो गए। पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान वहां रखी कुर्सियां फेंकी गईं। डंडों के साथ तोड़फोड़ कर दी गई। हमले में इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

सूचना मिलते ही थाना हरीपर्वत से अतिरिक्त पुलिसबल आ गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को लाठियों फटकारते हुए खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। सांसद के घर पर घेराव की तैयारी सुबह से ही की जा रही थी। एल्हादपुर में करणी सेना से

पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। वहां भी पुलिस ने इन्हें रोका था। इस बीच दोपहर को बड़ी संख्या में ये लोग सपा सांसद के हरीपर्वत क्षेत्र स्थित आवास तक पहुंच गए।

राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर एक तरफ सांसद के आवास पर हमला बोल दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईवे पर करणी सेना ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ यहां जमकर धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने बमुश्किल स्थिति पर काबू पाया।

सपा सांसद का संसद में बयान

रामजीलाल सुमन ने संसद में कहा था कि भाजपा के लोगों का तक्रिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आखिर, बाबर को लाया कौन। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान में लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो फिर तुम गद्दर राणा सांगा की औलाद हो। हम बाबर की आलोचना करते हैं। लेकिन, हम राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते?

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

'ब्रेस्ट छूना रेप नहीं...' फैसले में अमानवीय दृष्टिकोण

एजेंसी • नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा था कि ब्रेस्ट पकड़ना और लड़की के पायजामे की डोरी तोड़ना रेप या रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की और कहा कि इस फैसले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है और ये अमानवीय है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज

मसौह की पीठ ने कहा, 'हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसला लिखने वाले की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। ये फैसला तत्काल नहीं लिया गया था, बल्कि फैसला सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। इस प्रकार, इसमें विवेक का इस्तेमाल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हम आमतौर पर इस स्तर पर रोक (स्थगन) लगाने में देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के दायरे से बाहर हैं और अमानवीय दृष्टिकोण दिखाती हैं, इसलिए हम इन टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।



केंद्र और यूपी से मांगा जवाब

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है। अदालत ने कहा, "हम केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य और हाईकोर्ट के समक्ष पक्षकारों को नोटिस जारी करते हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल अदालत की मदद करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने 24 मार्च को विवादास्पद अदालती आदेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

यह था हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये विवादित फैसला दो लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया, जिन्हें रेप के आरोप में निचली अदालत ने तलब किया था। मामले में आरोपी पवन और आकाश ने कथित तौर पर 11 वर्षीय नाबालिग के ब्रेस्ट पकड़े। आरोपियों में से एक ने लड़की के पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। इस मामले में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने फैसला सुनाया कि केवल ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा अपराध किसी भी महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल के दायरे में आता है, जिसका भ्रम उससे निर्वस्त्र करना हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पर हमले के आरोपों के साथ-साथ POCSO एक्ट (गंभीर यौन उत्पीड़न) की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

एमआर-12 इसी साल बनेगी, मोरोद माचल में बनेगी नई अनाज मंडी भोपाल और धार रोड पर दो और ISBT बनेंगे ▶

प्राधिकरण का 88.12 करोड़ फायदे का बजट पेश

1500 करोड़ के काम होंगे

संवाददाता • इंदौर

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने बुधवार को बजट पेश कर दिया। खास बात ये कि इस बार 88.12 करोड़ के लाभ का बजट है। इसमें कुल अनुमानित प्राप्त 1597.00 करोड़ और कुल प्रस्तावित व्यय 1508.88 करोड़ दर्शाया गया है। इस साल सड़क निर्माण, स्टार्टअप पार्क, अनाज मंडी, ब्रिज सहित अन्य विकास कार्यों पर रुपये खर्च होंगे। सबसे ज्यादा राशि 432 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च की जाएगी। उज्जैन रोड को बायपास से जोड़ने के लिए इसी साल एमआर-12 सड़क बनाई जाएगी।

संभागयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि इस बजट में आईडीए की नई स्कीम का विकास, बेहतर ट्रैफिक और मास्टर प्लान

की सड़कों को बनाने, स्कीम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, ग्रीनरी का डेवलपमेंट, एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए ग्रीन बेल्ट का विकास और साथ ही गैर योजना मद में आई एंड कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के बारे में भी बजट में प्रावधान किया है।

सड़कों के लिए 432 करोड़, विद्युतीकरण के लिए 242 करोड़, पलायओवर के लिए लगभग 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। डिपोजिट वर्क के लिए लगभग 122 करोड़ है। ग्रीनरी के लिए 38 करोड़ रखे गए हैं। 2028 में सिंहस्थ के लिए मास्टर प्लान रोड एमआर-11, एमआर-12 पर पलायओवर प्राथमिकता में लिए गए हैं। हमने दो नए आईएसबीटी एक भोपाल रूट पर बायपास पर और दूसरा धार रोड पर चंदन नगर के आगे प्रस्तावित किया है। छावनी मंडी को मोरोद में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, वन मंडलाधिकारी प्रदीप मिश्रा, अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग शुभाशीष बनर्जी आदि मौजूद थे।



ये काम होंगे इसी साल

- सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा। 20 मंजिला बिल्डिंग में छोटी कंपनियों को स्पेस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एक कंवेनशन सेंटर और एक होटल भी इस स्कीम में प्रस्तावित है।
- शहर में चार सीएम राइज स्कूल भी प्राधिकरण बनाएगा। इसके लिए बजट में 46 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस योजना में सरकार ने

अहिल्य लाइब्रेरी के प्रीतमलाल दुआ सभागृह की परम्परा भी की जाएगी। टिगरिया बादशाह गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण भी प्राधिकरण करेगा। इसके अलावा शहर के मच्छी बाजार क्षेत्र में स्थित प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर व खजूरी बाजार के तुलसीदास मंदिर को भी प्राधिकरण संवारेगा।

नगर निगम का बजट 3 अप्रैल को

नगर निगम का बजट सम्मेलन 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे श्री अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह अटल सदन निगम मुख्यालय में बुलाया गया है। इसमें निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट महापौर पुष्पित्र भार्गव पेश करेंगे। इस मौके पर अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

एमआर-10 पर नया बस स्टैंड तैयार

संभागयुक्त दीपक सिंह के अनुसार इस साल शहरवासियों को एमआर-10 पर नए बस स्टेशन और वरिष्ठ जनों के कॉम्प्लेक्स की सुविधा मिल जाएगी। 32 फ्लैटों के इस कॉम्प्लेक्स में वाहनों की पार्किंग के अलावा फिजियोथैरेपी कक्ष, एंबुलेंस सेवा भी रहेगी।

शांट न्यूज

टमाटर की बंपर आवक, किसानों को मिल रहे दो रुपए किलो भाव

इंदौर। अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में टमाटर की फसल बोई है। इसके चलते अब मंडियों में टमाटर की आवक ज्यादा हो गई और डिमांड कम है। जो टमाटर पहले मंडियों में 30 रुपये किलो थोक में मिल रहे थे। अब वे एक-दो रुपये किलो में बिक रहे हैं। हालात यह है कि किसान मंडियों में टमाटर ला रहे हैं, लेकिन उचित दाम न मिलने के कारण वे उन्हें मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों को मंडियों तक टमाटर को परिवहन कर लाना भी महंगा पड़ रहा है। इस साल मौसम टमाटर के अनुकूल रहा। इस कारण इंदौर संभाग में रकबा बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में टमाटर का उत्पादन ज्यादा हुआ। दरअसल छह माह पहले इंदौर में टमाटर खरबी मंडियों में 80 से 100 रुपये किलो तक बिका था।

शौक पूरे करने के लिए रची अपहरण की झूठी कहानी

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शौक पूरा करने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचकर परिवार से फिरोती मांगने का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को फरियादी श्रीराम गुप्ता ने शिकायत की थी कि बेटा सतीश चौईथराम मण्डी में काम करता है। उसको किसी ने बंधकर बनाकर रखा है, उसे छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये फिरोती मांग कर रहे हैं। इस पर टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की। टीम द्वारा तत्काल मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली। पैसे देने के बहाने आरोपितों के बताए पते पर टीम पहुंची तो सतीश दोस्त आरुष आरौरा व तेजवीर सिंह के साथ था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों से कर्जा लिया।

किराए की कार हड़प ली, ट्रक चोरी की झूठी कहानी रची

इंदौर। एमआइजी इलाके में किराए पर कार लेकर हड़पने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। उधर खजराना इलाके में ट्रक खरीदने के बाद चोरी की झूठी कहानी गढ़कर ट्रक को कबाड़े में बेचने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया। पहले मामले में एमआइजी पुलिस ने सनी पिता जितेंद्र भंडारी निवासी रूस्तम का बगीचा की रिपोर्ट पर आरोपी अमित पिता नारायण प्रसाद सोनी निवासी अरण्य नगर स्कीम नंबर 78 के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपी अमित सोनी ने उससे कार किराए पर ले ली थी। कई माह तक न तो इसका किराया दिया और न ही उसका वाहन लौटाया। उधर दूसरे मामले में थाना खजराना पुलिस ने फरियादी लक्ष्मी पति तंवर सिंह गोयल निवासी पटेल नगर खजराना की रिपोर्ट पर आरोपी दीपक पिता सत्यनारायण कसेरा और शाहरुख कुरैशी निवासी मंदसौर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

100 करोड़ के घोटाले की जांच पूरी हुई नहीं, 10 करोड़ का नया केस आ गया

नगर निगम में फर्जी बिल मामला फिर आया सामने

संवाददाता • इंदौर

पिछले साल हुए 100 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है और नगर निगम में एक और फर्जी बिल घोटाला सामने आया है। 11 करोड़ के फर्जी बिल निगम की लेखा शाखा में भुगतान के लिए लगाए गए। निगम अफसरों ने मामला पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जिस नीव कंस्ट्रक्शन कंपनी का नया घोटाला सामने आया है। उसका कर्ताधर्ता मोहम्मद साजिद पुराने घोटाले में भी शामिल है और आरोपी भी है। नगर निगम के सहायक लेखापाल आशीष तायड़े की शिकायत पर एमजी रोड थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मार्च में नगर निगम में सबसे ज्यादा बिल लगाए जाते हैं और इस दौरान घोटाले की आशंका भी बनी रहती है, क्योंकि बिलों का सत्यापन ठीक से नहीं हो पाता। साजिद खान की तरफ से 185 बिल लगाए गए। जिसमें डेढ़ सौ से ज्यादा बिल फर्जी निकले। लेखा विभाग ने पुराने घोटाले से सबक लेकर बिलों की जांच शुरू की। यह फर्जी बिल 11 करोड़ रुपये के है। पुराने घोटाले में कंपनी को काली सूची में डाला गया है। इसके बावजूद पुराने बिल भुगतान के

मामला

लिए लगाए गए। बता दें कि पिछले साल पांच ठेकेदार एजेंसियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। 100 करोड़ से ज्यादा के पाइप लाइन, सड़क निर्माण के घोटाले का मामला सामने आया था। इस घोटाले में लेखा विभाग के अफसरों के अलावा एक अधीक्षक यंत्री भी शामिल था। घोटाले की फाइल नगर निगम के एक अधिकारी की कार से चोरी चली गई थी। इसके बाद यह घोटाला सामने आया था। अभी इसकी जांच जारी है।



लिए लगाए गए। बता दें कि पिछले साल पांच ठेकेदार एजेंसियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। 100 करोड़ से ज्यादा के पाइप लाइन, सड़क निर्माण के घोटाले का मामला सामने आया था। इस घोटाले में लेखा विभाग के अफसरों के अलावा एक अधीक्षक यंत्री भी शामिल था। घोटाले की फाइल नगर निगम के एक अधिकारी की कार से चोरी चली गई थी। इसके बाद यह घोटाला सामने आया था। अभी इसकी जांच जारी है।

बस स्टैंड ने कॉरिडोर तोड़ने के ठेके पर ब्रेक लगाया

नए टेंडर लाने की तैयारी

संवाददाता • इंदौर

बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए नगर निगम ऐसा टेंडर तैयार कर रहा है जिससे निगम पर खर्च का बोझ न आए। पहले तोड़ने वाले को ही रैलिंग और बस स्टॉप के स्टेशन दिये जा रहे थे। इसके बदले निगम को पैसा आता, लेकिन कॉरिडोर में बने बस स्टेशन विज्ञान एजेंसी के बनाए हैं। जिसका टेंडर समय पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यह संपत्ति निगम के हवाले कैसे होगी। बस स्टेशन ने कॉरिडोर तोड़ने के ठेके पर ब्रेक लगा दिया है। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के आदेश मिलने के बाद नगर निगम ने जीपीओ चौराहा पर कॉरिडोर की रैलिंग



हटाई थी। अब बची रैलिंग ही निगम के हिस्से आनी है। जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर के अनुसार कॉरिडोर की रैलिंग को तालाबों की पाल और नेहरू पार्क में ट्रेन के ट्रैक के आसपास लगाने की योजना है। कॉरिडोर की जगह सेंट्रल डिवाइडर का ठेका भी निकाला जा रहा है। कबाड़ में

फर्जी दस्तावेजों से कब्जा किया, फिर दुकान निर्माण कर किराए पर दे दी

दो आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

संवाददाता • इंदौर

लसूडिया इलाके में दो आरोपियों द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन पर फर्जी दस्तावेज के जरिए कब्जा जमाते हुए दुकान का निर्माण कर उसे किराए पर देने का मामला सामने आया है। मामले में बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज किया है।

लसूडिया पुलिस के मुताबिक मामला तुलसी नगर क्षेत्र में स्थित प्लॉट का है। पुलिस ने फरियादी विश्वास पिता कन्हैयालाल शर्मा (63) निवासी महालक्ष्मी नगर की रिपोर्ट पर आरोपी लक्ष्मी उर्फ सचिन मालवीय और वीर बहादुर पिता रामस्वरूप विश्वासका के खिलाफ

प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि आरोपी लक्ष्मी उर्फ सचिन मालवीय ने भूखंड क्रमांक 8 ए तुलसी नगर के नकली दस्तावेज तैयार कर लिए। उसने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अवैध कनेक्शन ले लिया और फरियादी का विद्युत मीटर तोड़कर फेंक दिया। आरोपियों ने फर्जी विक्रय लेख निर्मित कर भूखंड पर टीनशेड की दुकान बना ली और दुकान को किराए पर दे दिया। इस तरह फर्जी कृत्य कर अवैध लाभ अर्जित कर धोखाधड़ी की। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

महापौर बोले- पीएम के विजन को पूरा करने वाला इंदौर

विपक्षी भी मानने लगे ये बात

इंदौर। हमारे शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने कहा कि चेन्नई के अधिकारी कचरा प्रबंधन सीखने के लिए यूरोप नहीं मग्न के इंदौर जाएं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चेन्नई के अधिकारी कचरा प्रबंधन तकनीकों का अध्ययन करने के लिए यूरोप का दौरा करेंगे। चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पहले भी कई अध्ययन दौरे किए, लेकिन उनसे कोई ठोस बदलाव नहीं दिखा। उनके बयान पर महापौर पुष्पित्र भार्गव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। उनके मिशन को पूरा करने वाला इंदौर है। इंदौर सफाई मैनेजमेंट में देश के लिए रोल मॉडल है। देश का कोई भी शहर इंदौर आकर सफाई देखना या सीखना चाहता है तो उनका स्वागत है। महापौर ने कहा कि चिदंबरम ने चेन्नई की सफाई को लेकर कुछ सवाल उठाए और कहा कि इंदौर जाकर सफाई व्यवस्था देखना चाहिए। उन्होंने अच्छी बात को समझकर अच्छा करने के लिए कहा है। इंदौर में सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने वाला इंदौर है। अब तो विपक्षी भी इस बात को मानने लगे हैं।



केयर टेकर ही चोर निकला, 9 लाख कैश और सोने की चेन बरामद

लाखों रुपए झाड़ियों में छुपाए, कुछ गड्डियां लेकर चला गया था घूमने

संवाददाता • इंदौर

राऊ क्षेत्र के सिल्लिकॉन सिटी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घर का केयर टेकर ही निकला, जिसके कब्जे से 9 लाख नगदी व एक सोने की चेन पुलिस ने बरामद की है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अहमदाबाद सोमनाथ, भोपाल, उज्जैन आदि जगहों पर घूमने निकल गया था। डीसीपी व नो. 10 कुमार मीना ने बताया

वारदात

कि गत 11 मार्च को सिल्लिकॉन सिटी निवासी फरियादी अमित पिता आनन्द मिश्रा ने अपने घर के अन्दर रखे प्लाट खरीदने के टोकन के 12 लाख रुपये व एक सोने की चेन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वारदात के बाद से घर में काम करने वाला केयर टेकर केशव निवासी ग्राम नन्दराई जिला दमोह भी गायब है। फरयादी ने केअर टेकर पर चोरी का संदेह व्यक्त किया था। मामले में राऊ पुलिस द्वारा केस दर्ज कर संदेही आरोपी की तलाश की जा रही थी। संदेही को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी राऊ द्वारा टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा घटना के बाद से ही घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से विश्लेषण किया गया एवं संदेही केशव रजक की तलाश हेतु उसके संभावित स्थानों मेहर, नन्दराई, पथरिया, दमोह, विदीशा, भोपाल आदि स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा लगातार दबीश दा की गई, किन्तु संदेही केशव रजक का कोई पता नहीं चल पाया था। संदेही की तलाश हेतु पुलिस द्वारा मुखबिर को एक्टिव किया गया।



कहीं भागने की फिराक में था, तभी पकड़ा गया

इसी कड़ी में गत दिन पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध लड़का बैग लिये हुए राऊ बाईपास सेज युनिवर्सिटी के पास दिखाई दिया है, जो संदेही केयर केटर केशव रजक जैसा दिखाई दे रहा है। वह किसी साधन से कहीं जाने की तैयारी में है। मुखबिर की सूचना के अनुसार सेज युनिवर्सिटी ब्रिज के थोड़ा आगे एक लड़का दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल ने घेराबंदी कर पकड़ा। उसने अपना नाम केशव रजक निवासी नन्दराई थाना पथरिया जिला दमोह बताया तथा अपराध करना स्वीकार किया। उसने यह भी बताया कि चोरी के रुपए व सोने की चेन चुराकर सिल्लिकॉन सिटी से एक नया बैग खरीदकर उसमें रुपए व चेन रखकर भागा था। रुपये ज्यादा होने से युनिवर्सिटी के सामने मन्दिर के पीछे सुनसान जगह पर झाड़ियों में छुपाकर पथरों से दबा दिया था। बैग में से खर्च एवं घूमने फिरने के लिये चार पांच गड्डी निकाल ली थी।

लसूडिया में हादसा : 25 फीट की ऊंचाई से गिरा था

पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत

संवाददाता • इंदौर

लसूडिया इलाके में बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। 20 मार्च की रात देवास नाके के पास बिजली पोल पर चढ़कर कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। वह 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल बांबे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को



देखते हुए एम्बयू रैफर कर दिया गया। मंगलवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लसूडिया पुलिस के अनुसार, 35क की पहचान हरिनारायण (35) पिता शिवराम अग्रवाल निवासी अरडिया ग्राम के रूप में हुई है। हरिनारायण पिछले चार

गिर गया। इससे सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई।

परिवार में छाया मातम

हरिनारायण मूल रूप से शाजापुर जिले के पास के एक गांव का रहने वाला था। उनकी मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिवार में पत्नी माया अग्रवाल और एक बेटा अनमोल है। इसके अलावा, उसके तीन भाई भी हैं, जो अलग रहते हैं। हरिनारायण अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा था, लेकिन इस हादसे ने उनके जीवन को गहरे दुख में डाल दिया है।

दुर्घटना या लापरवाही : पुलिस कर रही जांच

लसूडिया पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह हादसा महज एक दुर्घटना थी या फिर इसमें किसी की लापरवाही भी जिम्मेदार थी। फिलहाल, घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि पीड़ित के परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

देश के युवा अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध करें- मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग

सारंग ने किया दो दिवसीय 'विकसित भारत युवा संसद' कार्यक्रम का शुभारंभ

संवाददाता • भोपाल

मध्यप्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को दो दिवसीय राज्य स्तरीय 'विकसित भारत युवा संसद-2025' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 'विकसित भारत 2047' के संकल्प का आह्वान किया है। यह संकल्प तभी साकार होगा जब देश के युवा अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध करें। मंत्री श्री सारंग ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के युवा ही देश के उज्वल भविष्य के निर्माता हैं। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'विकसित भारत युवा संसद' का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जो नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही कर्तव्यों का पालन भी अनिवार्य है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।



युवाओं को मिला राष्ट्र निर्माण में योगदान का मंच

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा मंच है, जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपने विचार और दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन न केवल युवाओं को सैधनिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने में सहायक होगा, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक करेगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री सारंग ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने विचारों को आत्मसात करें और भारत के नवनिर्माण में सार्थक योगदान दें।



राज्य स्तरीय युवा संसद में 200 प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 20 नोडल जिलों से चयनित 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा और संविधान दिवस के 11 संकल्प विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी प्रतिभागियों को अपने वक्तव्य के लिए तीन मिनट का समय दिया गया। इस दो दिवसीय युवा संसद के माध्यम से प्रदेश स्तर पर शीर्ष 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रीति पाठक, विधायक श्री अशीष शर्मा, मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह, सचिव श्री अरविंद शर्मा, डॉ. अशोक कुमार श्रोती, नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्री राकेश सिंह तोमर सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

शुभारंभ

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा मंच है, जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपने विचार और दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन न केवल युवाओं को सैधनिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने में सहायक होगा, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक करेगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री सारंग ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने विचारों को आत्मसात करें और भारत के नवनिर्माण में सार्थक योगदान दें।

शॉर्ट न्यूज

शोक पूरे करने के लिए रची अपहरण की झूठी कहानी

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शोक पूरा करने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचकर परिवार से फिरोती मांगने का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को फरियादी श्रीराम गुप्ता ने शिकायत की थी कि बेटा सतीश चौईश्राम मण्डी में काम करता है। उसको किसी ने बंधकर बनाकर रखा है, उसे छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये फिरोती मांग कर रहे हैं। इस पर टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की। टीम द्वारा तत्काल मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली। पैसे देने के बहाने आरोपितों के बताए घरे पर टीम पहुंची तो सतीश दोस्त आरुष आरोरा व तेजवीर सिंह के साथ था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि अपने शोक पूरे करने के लिए लोगों से कर्जा लिया।

मेट्रो ट्रैक से लाखों के कॉपर जाईंट चुरा ले गए

इंदौर। शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू होने से पहले ही चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए ट्रैक पर लगे कॉपर एक्सटेंशन चुराकर ले गए। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। चोरी की वारदात हीरानगर थाना क्षेत्र में आने वाले आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से चन्द्रपुत मौर्य चौराहा मेट्रो स्टेशन के बीच हुई, जहां मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर लगाये गए 12 कॉपर एक्सटेंशन चोर चुराकर ले गए। चोरी का पता उस वक्त चला, जब मेट्रो के ट्रैक इंस्टॉलेशन करने वाली ठेकेदार कंपनी का इंजीनियर निरीक्षण करने पहुंचा। मामले में पुलिस ने फरियादी जितेंद्र पिता शिवराम दुबे निवासी प्लाजो पार्क रेसीडेन्सी पिपलिया कुमार की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

कॉलेज बस लहराई तो राहगीरों ने रोका, चालक को धरदबोचा

इंदौर। रोड पर एक कॉलेज बस को राहगीरों ने रुकवाकर अंदर बैठे स्टाफ और विद्यार्थियों को बाहर निकाला। बस पलासिया के समीप लहराई और फिर एक अटो को कट मारा तो अंदर बैठे टीचर व राहगीरों ने समझ लिया कि चालक की स्थिति सामान्य नहीं है तथा उन्होंने बस को रोककर पुलिस को मौके पर बुलवा लिया। घटना कनाडिया रोड इलाके की है, जहां चमेलीदेवी कॉलेज की बस एम्पी 09 एफए 2694 (रूट क्र. 8) के चालक पर लोगों ने नशे में होने का आरोप लगाया है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। राहगीरों ने बस को रोककर अंदर बैठे स्टाफ व विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंचवटी के बाद एलआईजी से विद्यार्थियों को बैठाया, जिसके बाद बस अंधागति से दौड़ाते हुए पलासिया चौराहे लेकर आया, जहां बस लहराई तो चालक शंका के घेरे में आ गया। कनाडिया रोड पर हनुमान मंदिर के समीप सड़क किनारे चल रही ऑटोरिक्षा को भी ड्रायवर ने कट मारा।

भारत गौरव ट्रेन से करें अमृतसर और वैष्णोदेवी की तीर्थ यात्रा

भोपाल मंडल के स्टेशनों से मिलेगी सीधी सुविधा

संवाददाता • भोपाल

रानी कमलापति, इटारसी, विदिशा और बीना से होकर गुजरेगी विशेष ट्रेन - तीर्थ यात्रियों के लिए सुनहरा अवसर आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा "उत्तर दर्शन के साथ गुरुकुपा (अमृतसर) यात्रा" के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों रानी कमलापति, इटारसी, विदिशा एवं बीना से होकर गुजरेगी। यह यात्रा विशेष रूप से



सुविधा

मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक और लाभकारी है। 27 मई 2025 को रीवा से रवाना होने वाली यह विशेष पर्यटन ट्रेन, रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, रानी कमलापति, विदिशा, बीना और झंसी होते हुए चलेगी। इन स्टेशनों से यात्री इस पवित्र यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 09 रातें / 10 दिन की इस धार्मिक यात्रा में यात्रियों को मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णो देवी के दर्शनस्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस यात्रा का शुल्क प्रति व्यक्ति 17,600/- (स्लीपर - इकॉनॉमी श्रेणी), 28,700/- (3AC - स्टैंडर्ड श्रेणी), एवं 37,800/- (2AC - कम्फर्ट श्रेणी) निर्धारित

किया गया है। इस शुल्क में भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी कोच में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड एवं ऑफ-बोर्ड शाकाहारी भोजन, पर्यटन स्थलों तक गुणवत्तायुक्त वातानुकूलित बस सुविधा, यात्रा कार्यक्रम अनुसार आवास व्यवस्था, अनुभवी दूर एस्कॉर्ट्स की सेवा, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग जैसी सभी सुविधाएँ सम्मिलित हैं। यह एक पूर्णतः सर्वसमावेशी टूर है। इस पवित्र यात्रा में भाग लेने के इच्छुक यात्री अपनी बुकिंग आई.आर.सी.टी.सी. की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन या किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से करा सकते हैं। यह ट्रेन न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि भोपाल मंडल के यात्रियों को उनके नजदीकी स्टेशनों से ही सीधी सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे यात्रा और भी सुगम और सुलभ हो जाती है।

जंगल में लावारिस मिला पेटलावद का बच्चा अब जाएगा अमेरिका

संवाददाता • इंदौर

छह महीने पहले पेटलावद (झाबुआ) के सरकारी अस्पताल में लावारिस हालत में मिले नाबालिग को आखिरकार एक नया परिवार मिल गया है। बुधवार को यह मासूम अपने नए माता-पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाते वाला है। इस दंपति ने न केवल बच्चे को अपनाया है, बल्कि उसे एक नया जीवन और सुरक्षित भविष्य भी प्रदान किया है। पासपोर्ट की औपचारिकताएँ पूरी होते ही यह परिवार अमेरिका रवाना होगा, जहां बच्चे को माता-पिता का भरपूर स्नेह और देखभाल मिलेगी। यह बच्चा क्लेफ्ट पैलेट (कटे तालू) और क्लेफ्ट लिप (कटे होंठ) जैसी जन्मजात स्वास्थ्य समस्या के साथ पैदा हुआ था। जन्म के दो महीने बाद ही उसके जैविक माता-पिता ने उसे पेटलावद के सरकारी अस्पताल



में लावारिस छोड़ दिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने उसे इंदौर की संजीवनी सेवा संगम संस्था को सौंप दिया, जहां उसका इलाज किया गया। संस्था ने न केवल उसका संचालित उपचार करवाया, बल्कि उसे स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

माता-पिता की तलाश पूरी नहीं हो सकी

संस्था द्वारा लंबे समय तक बच्चे के जैविक माता-पिता को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। झाबुआ जिले की बाल कल्याण समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संजीवनी सेवा संगम संस्था को बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। संस्था में कार्यरत महिला केयरटेकर्स ने उसे अपनी संतान की तरह पाला और उसे हर प्रकार की सुविधा और देखभाल प्रदान की। इस दौरान बच्चे की अच्छी परवरिश के साथ उसके मानसिक और शारीरिक विकास का भी विशेष ध्यान रखा गया। संस्था के अथक प्रयासों के कारण अब यह बच्चा एक अमेरिकी दंपति के परिवार का हिस्सा बनने जा रहा है। दंपति बच्चे के साथ अमेरिका के लिए रवाना होगा। अमेरिकी दंपति ने पूर्व में भी एक बालक और एक बालिका को अमेरिका में गोद लिया है। बच्चों के पिता एक कंपनी में जांब करते हैं। मां हाउस वाइफ हैं। अब वे भारत में तीसरा बच्चा गोद ले रहे हैं। दंपति का कहना है कि उन्हें भारतीय संस्कृति से काफी लगाव है। संजीवनी सेवा संगम 1981 से संचालित है। संस्था अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए काम करती है। संस्था बच्चों को रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधाएं देती है।

केंद्र के पोर्टल में खामी

किस रोग से हुई मौत, मृत्यु प्रमाण पत्र में नहीं उल्लेख

संवाददाता • इंदौर

तो विभाग के वर्तमान रजिस्ट्रार वीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान में जो माहिती मृतक के परिजनों से दर्ज की जाती है उसमें मृतक के आधार प्रमाण पत्र हेतु लिया जाता है साथ ही पते के साथ मृत्यु दिनांक स्थान का उल्लेख रहता है साथ ही मृत्यु के कारण भी दर्ज करवाया जाता है। दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु की जानकारी प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होने से क्लेम लेने में भी परेशानी आती है। इसके अलावा शासन की योजनाओं में भी पात्र होने के लिए ये आवश्यक है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कारण का स्पष्ट उल्लेख होगा। असाफी होगी। जो पोर्टल है वह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमें ये सुधार हो। इसकी नितांत आवश्यकता है।

नगर निगम के जन्म मृत्यु विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र में एक बड़ी खामी सामने आई है। इस आशय की जानकारी सामने आई

जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में एक खामी सामने आई है। प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं रहता कि संबंधित की मृत्यु किस कारण से हुई है जबकि श्मशान घाट पर भरे जाने वाले कॉलम में मृत्यु के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य है। विभाग में ये भले ही दर्ज किया जाता है किंतु प्रमाण पत्र में उल्लेख होने से मृतक के परिजनों को आसानी होगी क्योंकि अनेक योजनाओं में मृत्यु के कारण की वजह से बीमा राशि का प्रावधान होता है। नगर निगम के जन्म मृत्यु विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र में एक बड़ी खामी सामने आई है। इस आशय की जानकारी सामने आई

मौजूदा गतिविधियों और योजनाओं के बारे में दी जानकारी

RSS के शताब्दी वर्ष पर सालभर होंगे विशेष कार्यक्रम

संवाददाता • इंदौर

मालवा प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री ने प्रेसवार्ता के दौरान संघ की हालिया गतिविधियों और योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ के कार्यों में लगातार विस्तार हो रहा है, और इस वर्ष संघ की शाखाओं और सप्ताहिक मिलनों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक 21 से 23 मार्च तक बैंगलुरु के पास चेन्नहल्ली में स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में संपन्न हुई। इस बैठक में संघ की कार्यस्थिति और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। देशभर में 51,570 स्थानों पर 83,129 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जो पिछले वर्ष से 10,000 अधिक हैं। इस वर्ष संघ में 2,453 स्वयंसेवकों को संघ कार्य के विस्तार के लिए दो साल के लिए खुद को समर्पित किया। संघ की वेबसाइट के जरिए 12,72,453 लोग अब तक संघ से जुड़ चुके हैं, जिनमें 46,000 महिलाएं शामिल हैं।



मालवा में संचालित हो रहीं नई गतिविधियां

मालवा प्रांत में विशेष रूप से बढ़ते हुए शाखाओं और सेवा गतिविधियों का उल्लेख किया, जहां 3046 स्थानों पर 4636 शाखाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने संघ के सामाजिक और सेवा कार्यों की भी चर्चा की, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आगामी विश्व संघ शिविर का ऐलान बैठक में आगामी विश्व संघ शिविर का भी ऐलान किया गया, जो इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित होगा, जिसमें 60 देशों से

दो हजार स्वयंसेवकों के आने की संभावना है। संघ ने विभिन्न सेवा गतिविधियों को लेकर भी अपने कार्यों का उल्लेख किया। इस समय देशभर में 89,706 सेवा गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुम्भ के दौरान संघ ने विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया, जिसमें निःशुल्क नेत्र परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य शामिल थे।

नगर निगम में दिया धरना

दुकान के बाहर डमी उठाने से व्यापारियों नाराज



संवाददाता • इंदौर

फुटपाथ दुकानों के खिलाफ शिकायत की थी

राजवाड़ा क्षेत्र में कपड़ा दुकान से डमी उठाने के बाद निगमकर्मियों और व्यापारियों के बीच जमकर बहस हुई। व्यापारियों ने निगमकर्मियों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। नाराज व्यापारी अपनी शिकायत नगर निगम के कार्यालय में लेकर गए। मु ख य । ल य पहुंचे, जहां वे करीब ढाई घंटे तक धरने पर बैठे रहे। व्यापारियों ने पूरे मामले की शिकायत निगमायुक्त और अपर आयुक्त से की। अपर आयुक्त ने वीडियो के आधार पर जांच का आश्वासन दिया है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा क्षेत्र की एक कपड़ा दुकान में रखे डमी उठा लिए, जिससे मामला तूल पकड़ गया। व्यापारी एकजुट हो गए और निगमकर्मियों की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर नगर निगम मुख्यालय शिकायत करने पहुंच गए। व्यापारियों का आरोप था कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है।

अक्षय जैन ने बताया कि जिस व्यापारी की दुकान से डमी उठाई गई थी, उसने कुछ दिन पहले फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों के खिलाफ नगर निगम में शिकायत की थी। इसके बाद, रिमूल टीम ने बुधवार को दुकानों को चिह्नित कर शिकायतकर्ता की दुकान से जबर्न डस्टले (डमी) हटा लिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अपर आयुक्त लता अग्रवाल को सौंपा गया। व्यापारियों ने मांग की कि फुटपाथ पर अतिक्रमण न होने दिया जाए।

कर रहे जांच - अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि राजवाड़ा व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि शिकायत लेकर आए थे। उनका कहना था कि निगमकर्मियों धर्मद बेस ने व्यापारियों को पहचान कर चुनिंदा दुकानों से सामान निकाला। व्यापारियों ने इस संबंध में वीडियो भी दिखाए, जो मेयर और निगमायुक्त को भी भेजे गए हैं। निगमायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की जांच की जाए। सुपरवाइजर की जगह अब सहायक रिमूल अधिकारी विनीत तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बहस

राजवाड़ा क्षेत्र में कपड़ा दुकान से डमी उठाने के बाद निगमकर्मियों और व्यापारियों के बीच जमकर बहस हुई। व्यापारियों ने निगमकर्मियों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। नाराज व्यापारी अपनी शिकायत नगर निगम के कार्यालय में लेकर गए। मु ख य । ल य पहुंचे, जहां वे करीब ढाई घंटे तक धरने पर बैठे रहे। व्यापारियों ने पूरे मामले की शिकायत निगमायुक्त और अपर आयुक्त से की। अपर आयुक्त ने वीडियो के आधार पर जांच का आश्वासन दिया है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा क्षेत्र की एक कपड़ा दुकान में रखे डमी उठा लिए, जिससे मामला तूल पकड़ गया। व्यापारी एकजुट हो गए और निगमकर्मियों की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर नगर निगम मुख्यालय शिकायत करने पहुंच गए। व्यापारियों का आरोप था कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है।

मुख्यमंत्री ने 1127 करोड़ की लागत की औद्योगिक इकाइयों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

कारोबार में कमिटमेंट का अधिक महत्व : डॉ. यादव

संवाददाता • भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की कृपा से देश और प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जयिनी में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ था। इसके बाद क्रमवार संभागीय मुख्यालयों पर 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

इन आरआईसी में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 'विकसित भारत' को साकार करने प्रदेश में 1127.24 करोड़ रुपए के निवेश से 26 विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह परियोजनाएँ उज्जैन को एक नया औद्योगिक आयाम देंगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा। इन इकाइयों से हमारे लगभग 5046 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को समाहित कर प्रदेश में स्थित भारत के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक

सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीडीपी) का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विक्रम व्यापार मेला उज्जैन में आयोजित औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम का संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि व्यापार वचन से होता है, व्यापार में वचन का ही सर्वाधिक महत्व है। मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए वचनों को पूरा करने संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 4.41 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने का जो सपना देखा है, वो साकार हो रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर जिलों को मिलाकर एक नए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। जबलपुर, ग्वालियर और उनके आस-पास के जिलों का भी विकास मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में भविष्य में किया जाएगा। इससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।



प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 का हुआ सफल आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। जीआईएस में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 नई औद्योगिक नीतियों की शुरुआत की। समिट के दौरान 70 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग हुई और प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो 17 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे। जीआईएस में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए विगत एक माह में 19 नवीन औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

बड़ी संख्या में लोगों ने की खरीद फरोख्त

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में विक्रमोत्सव-2025 का आयोजन भी किया जा रहा है। विक्रम व्यापार मेले में भी व्यापार व्यापक स्तर पर हो रहा है और बहुत अधिक संख्या में गाड़िया बिक रही है। अगले कुछ वर्षों में हम भव्य स्तर पर सिंहस्थ-2028 महापर्व का भी आयोजन करेंगे। आस्था का ये महाकुंभ अर्थव्यवस्था को गति देने में इतिहास लिखेगा और उज्जैन को प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। इस वर्ष 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है, जो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने के कार्य के लिए है। लाइली बहाना हमारे प्रदेश का गौरव है, बजट में लाइली बहानों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में अमूल द्वारा दूध प्र-संस्करण का कारखाना भी स्थापित किया गया है। प्रदेश की सांची डेयरी को भी अमूल की तर्ज पर विकसित कर सांची को हम प्रदेश की पहचान बनाएंगे। उज्जैन में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा श्री महाकाल महालोक बनाए जाने के बाद धार्मिक पर्यटन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 से अभी तक जिले में 60 करोड़ से अधिक धार्मिक पर्यटक आए हैं जिससे जिले में होटल व्यवसाय ने भी बहुत तस्करी की है।

शांट न्यूज तीन वर्ष में 507 प्रकरण न्याय पर भारी साजिश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस कोर्ट में फर्जी गवाह पेश कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने पिछले 3 साल में 507 आपराधिक मामलों में फर्जी गवाह पेश किए हैं। शहर में हर थाना क्षेत्र में फर्जी गवाह मौजूद है, जिन्हें पुलिस किसी भी मामले में गवाह बना देती है। मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर का रहने वाला एसपी कुशवाहा 100 पुलिस केस में गवाह हैं। मुरार पुलिस ने एसपी कुशवाहा को पुलिस रक्षा समिति का कार्ड बनाकर दे दिया है। हैरत की बात है कि पुलिस रिकॉर्ड में एसपी कुशवाहा 100 घटनाओं के दौरान घटना स्थल पर मौजूद गवाह है। एसपी कुशवाहा ने बताया कि मैं बेरोजगार हूँ। पुलिस अपनी मर्जी से मुझे गवाह बना देती है। एसपी कुशवाहा के परिजन हैरान परेशान हैं कि उनके बेटे को पुलिस ने 100 केस में गवाह बना रखा है।

वृद्धा ने कलेक्ट्रेट से मांगी इच्छामृत्यु

नरसिंहपुर। एमपी के नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट की चौखट पर माथा पटक कर 90 साल वृद्धा ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि जब न्याय नहीं दे सकते तो मृत्यु दे दो। बुजुर्ग को देखकर सभी हैरान हो गए। बुजुर्ग महिला ने जनसुनवाई के दौरान यह गुहार लगाई थी। आवेदक वृद्धा के मुताबिक न्याय पाने की आस में भटकने के चलते अब इच्छा मृत्यु मांगना ही एकमात्र रास्ता है। वृद्धी गवाह की रहने वाली काट लेते और खेती नहीं करने देते। पीड़ित वृद्ध महिला कुंजकुवर बाई ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शिकायत के बाद भी सिहोरा पुलिस में सुनवाई नहीं हुई। वृद्धा कलेक्टर शीतला पटेल की जनसुनवाई में पहुंची थी।

बच्चों में बढ़ती जंक फूड की लत का मुद्दा विधानसभा में गुंजा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में बच्चों के बीच जंक फूड की बढ़ती खपत और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। विधानसभा में इस मुद्दे को जबलपुर (उत्तर) से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या पिछले छह महीनों में फास्ट फूड में मिलावट की जांच के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है? इस चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे राजेंद्र शुक्ला ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जख्मत पर बल दिया। विधायक अभिलाष पांडे ने सदन को बताया कि राज्य में फास्ट फूड की खपत तेजी से बढ़ रही है।

विधायकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, सरकार लेने जा रही है ये बड़ा फैसला

संवाददाता • भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार अब विधायकों के लिए घर और गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी करने की तैयारी में हैं। अब विधायक 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। खास बात यह है कि जो विधायक 25 लाख व 15 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, बाकी अनुदान के तौर पर सरकार भरेगी। जो विधायक 50 लाख व 30 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 2% ब्याज अनुदान मिलेगा, बाकी ब्याज विधायक को खुद भरना पड़ेगा। कर्ज चुकाने की मियाद भी 5 साल से बढ़कर 10 साल की जा सकती है। विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति के शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर हाल ही में वित्त विभाग ने कुछ संशोधन कराए



फैसला

हैं। संसदीय कार्य विभाग ने संशोधन के साथ फाइल विधानसभा को भेज दी है। अब नया प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय से संसदीय कार्य विभाग को भेजा जाएगा, जहां से कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसी माह 3 मार्च को अपनी राय दी थी, जिसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने 10 मार्च को विधानसभा को पत्र भेजा। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे 'ए फ्लॉ' श्रेणी में रखते हुए तेजी से आगे बढ़ाया गया है।

है। मजदूरों की बात यह है कि विपक्षी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनप्रतिनिधियों सुविधा के लिए इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। विधायकों को पहले से कई सुविधाएं मिलती हैं। वेतन व भत्ते मिलाकर 1 लाख से ज्यादा मिलता है। इसके अलावा राज्य के भीतर असीमित मुफ्त यात्रा और सालाना 10,000 किमी हवाई यात्रा फ्री होती है। सत्र के दौरान हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।

पुलिस ने बकरियों को मार डाला!

पकड़कर कमरे में किया बंद, छोड़ने के लिए मांग रहे थे रिश्वत...

संवाददाता • रीवा

मध्य प्रदेश के रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रौसर में पुलिस की कार्रवाई के बाद कमरे में बंद करीब सौ से अधिक बकरा-बकरियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए और पुलिस पर घूस लेने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना पर पुलिस ने कहा कि जानवरों को कार्रवाई के बाद एक बाड़े में रखा गया था। जिनमें से कुछ की मौत हो गई। जानवरों का पोस्टमार्टम करारक मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पूरे मामले को लेकर व्यापारियों ने कहा कि चोरहटा पुलिस ने अटरिया बाईपास पर ट्रक पकड़ा था। जिसमें करीब 315 बकरा और बकरियाँ लोड थीं जिन्हें चोरहटा थाने ले जाया गया। इसके बाद अवैध तरीके से बकरियों को ले जाने को लेकर कार्रवाई की गई। मना करने के बावजूद रौसर गांव के दो कमरों में बकरा और



बकरियों को बंद कर दिया गया। लापरवाही पूर्वक जानवरों को बंद कर दिया गया था। व्यापारियों ने बताया कि आज सुबह जब वह मौके पर पहुंचे तो उनके करीब 150 से ज्यादा बकरा और बकरियों की मौत हो चुकी थी। इस घटना का आरोप व्यापारियों ने चोरहटा थाना पुलिस पर लगाया है।

पुलिस पर लगा रिश्वत लेने का आरोप

व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में उनसे बीस हजार नगद जबकि बीस हजार फोन पे पर लिए गए थे। जिसकी जानकारी व्यापारियों ने दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 24 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जानवरों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। उनके साथ क्रूरता हो रही है। जिसके बाद चोरहटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में लोड 315 बकरे और बकरियाँ को जब्त कर पशु क्रूरता सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिवपुरी जिले में हैरान करने वाला मामला आया सामने

पत्नी को पीट रहा था, मदद के लिए पहुंचा व्यक्ति, उल्टा भेजा जेल

संवाददाता • शिवपुरी

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, पति-पत्नी का झगड़ा चल रहा था, पति अपनी पत्नी को पीट रहा था। इसी दौरान एक अंधेड़ व्यक्ति ने देखा तो उसने गुस्से में लाल होकर पीटने वाले पति के साथ मारपीट कर दी और उसके सिर पर जूते रखकर भरे बाजार में जुलूस निकलवा दिया। वहीं ये अंधेड़ व्यक्ति को भारी पड़ गया और अब पुलिस की कार्रवाई के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ गई। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में एक अंधेड़ ने पति द्वारा पत्नी को पीटने का विरोध किया। व्यक्ति की मंशा थी कि पत्नी पर हाथ उठाने वाले पति को सबक मिलेगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। पुलिस ने अंधेड़ के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल, मंगलवार को जिले की कोलारस तहसील के रेलवे स्टेशन पर पति-पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पति-पत्नी को पीट रहा था। यह एक अंधेड़ व्यक्ति को रास नहीं आया और उसने पति को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की फिर उसके सिर पर जूते रखकर जुलूस निकलवा दिया। इस पर कोलारस पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बीच में पड़े व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अंधेड़ के खिलाफ पुलिस का एक्शन

बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पति-पत्नी के झगड़े के बीच नहीं पढ़ना चाहिए। शायद यह बात इस अंधेड़ ने सही नहीं मानी। यही वजह थी कि पति-पत्नी के झगड़े में बेवजह बीच में आ गया और पति अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर पीट रहा था उसे सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही सबक सीखने को मजबूर हो गया। कानूनी कार्रवाई का शिकार हुए पति-पत्नी के झगड़े के बीच में पड़े अंधेड़ व्यक्ति नाम ओमप्रकाश रजक बताया जा रहा है, जो की गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है।



पति-पत्नी के झगड़े में फंसा

पुलिस के मुताबिक, अंधेड़ पति के साथ मारपीट इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी को पीट रहा था। वहीं इस मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि अंधेड़ की मंशा थी कि पत्नी को पीटने वाले पति को सबक मिलेगा, लेकिन वह भूल गया कि किसी के सिर पर जूते रखकर जुलूस निकालना कानूनी अपराध है। यही वजह थी कि पुलिस को मजबूरी में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पति-पत्नी का जुलूस निकालने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए अलग-अलग कानूनी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।

पति-पत्नी का निकवाया था जुलूस

पति पत्नी गुना मध्य प्रदेश की रहने वाले है। पत्नी अपने पति के साथ भिड़ भुंरना में मजदूरी करने जा रहे थे। उनकी लड़की की शादी शिवपुरी जिले में हुई है। रास्ते में रुके और सोचा की बेटी से मिलकर जाएंगे, लेकिन पति-पत्नी में सहमति नहीं बनी। यही वजह थी कि दोनों के बीच झगड़ा हो गया और पति अपनी पत्नी को साथ मारपीट करने लगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर हो रही इस मारपीट के बीच में एक व्यक्ति पड़ा और उसे पति-पत्नी के झगड़े के बीच में आना और उनका जुलूस निकलवाना भारी पड़ गया।

पीएम आवास योजना सर्वे में नाम जोड़ दो...

सुन पंचायत सचिव बुजुर्ग महिला को पीटा

संवाददाता • सीधी
मध्य प्रदेश में पंचायत कर्मियों बेलगाम हो चुके हैं। शासन की योजनाओं का लाभ मांगने पर हितग्राहियों की पिटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीधी जिले में हुई महिला हितग्राही की वेदम पिटाई के जख्म बयां कर रहे हैं। अब पीड़ित महिला सीधी जिला प्रसासन से इंसाफ मांग रही है। दरअसल, पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे में नाम जुड़वाने को कहा, तो पंचायत सचिव रोजगार सहायक और एक



बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार

एक हफ्ते तक चले इलाज के बाद भी महिला पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। पीड़ित रामरती रजक बुजुर्ग हैं जिन्हें शासन की वृद्धा पेंशन योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक का लाभ पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस ग्राम पंचायत में रामरती रजक के ही सगे संबंधी गांव के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक हैं। ऐसे में पुराने विवाद और आपसी रंजिश के चलते दोनों कर्मियों इस पत्र महिला हितग्राही को शासन की तमाम योजनाओं से अपात्र कर वंचित कर दिया है। आरोपियों ने 14 मार्च को बुजुर्ग महिला की वेदम पिटाई कर दी। महिला की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला हितग्राही का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए सर्वे के लिए कहा तो पंचायत सचिव कुमार रजक रोजगार सहायक जगदीश रजक और एक अन्य व्यक्ति ने लाठी डंडों से पीटा।

गुहार

फिर लाठी डंडों से बुजुर्ग महिला को पिटाई कर दी। मामले में जमोड़ी पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वाले पंचायत सचिव रोजगार सहायक और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सीधी जनपद क्षेत्र की कारगोल ग्राम पंचायत में पंचायत कर्मियों की मनमानी कुछ इस कदर हावी है कि हितग्राहियों की योजनाओं के लाभ मांगने पर पिटाई कर रहे हैं। सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हाथों में आवेदन लिए महिला हितग्राही राम रती रजक खड़ी रही। उनके हाथ में चोट के गहरे जख्म भी थे।

न्यूज कॉलम

एक्शन मोड में नगर निगम अब यहां चला बुलडोजर

रायपुर। अविध कंस्ट्रक्शन को लेकर पिछले कुछ दिनों से रायपुर नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज भी नगर निगम के अमले ने बुलडोजर एक्शन लेते हुए अविध निर्माण पर कार्यवाई की है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप को आदेशानुसार और जोन 8 जोन कमिश्नर एके हालदार के निर्देशन पर वार्ड नम्बर 21 शहीद भगत सिंह वार्ड के पंचधाम मन्दिर के पास श्रीमती बीना सिंह द्वारा लगभग 6000 वर्गफीट भूखंड क्षेत्र में बिना अनुमति किये गए निर्माण को हटाए जाने की कार्यवाई की गई। इसी तरह आज श्रीमती मंजु अग्रवाल द्वारा स्वीकृति के विपरीत निर्माण को हटाए जाने की कार्यवाई की गयी है एवं पार्किंग क्षेत्र में निर्मित सीढ़ी एवं शटर को हटाया गया है एवं स्थल भवन स्वामी को भूतल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रायपुर नगर निगम ने थोक सब्जी मंडी में बनी अविध दुकानों पर भी बुलडोजर कार्यवाई की थी।

मरम्मत का इंतजार कर रहा मुंगेली-बिलासपुर के बीच बना अंग्रेजों के जमाने का पुल



मुंगेली। अंग्रेजों को तो भारत छोड़े 75 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनके किए गए निर्माणों की उपयोगिता जिम्मेदारों के नकारेपन का सबूत है। ऐसा ही एक मॉडल मुंगेली और बिलासपुर को जोड़ने वाला पुल है। अंग्रेजों के जमाने में बन यह पुल आज अपनी बदहाली पर आसू बहा रहा है। बरेला और तखतपुर के बीच इस पुल को नए सिरे से बनाने का मूल स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन न तो नेता को और न ही किसी अधिकारी को परवाह है। बीच-बीच में दिखाने के लिए मरम्मत कार्य कर छोड़ दिया जाता है। यही नहीं इस पुल से ही नहीं बल्कि शहर के बीच से भारी वाहनों का गुजरना प्रतिबंधित है। फिर भी घड़िल्ले से गुजर रहे हैं। केवल सड़क पुल ही अपनी मरम्मत की बांट नहीं जोह रहा है, बल्कि पुल पर जगह-जगह जानलेवा गड्डे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसकी भी समय से साथ मरम्मत करने की जरूरत है। बातचीत में स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव का गृह जिला होने के बावजूद दिग्गज जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। जबकि बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी इसी पुल को क्रॉस कर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन चमचमती कार से नीचे झुकने की उन्हें भी फुर्सत कहाँ है?

जमीन की नई गाइडलाइन दर तय करने से पहले बाजार मूल्य का आकलन, 31 मार्च तक मंगाए प्रस्ताव

संवाददाता ● रायपुर

छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति व जमीन की सरकारी कीमत बढ़ाने की तैयारी है। राज्य में निवेश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इस इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों ने कुल 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस बैठक में कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में अपनी परिचयनाएं शुरू करने को लेकर रुचि दिखाई, जिससे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़ 3700 करोड़ से अधिक के हुए करार

सीएम विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से किया संवाद

संवाददाता ● रायपुर

छत्तीसगढ़ को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। राज्य में निवेश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इस इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों ने कुल 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस बैठक में कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में अपनी परिचयनाएं शुरू करने को लेकर रुचि दिखाई, जिससे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और द इंडियन एंटरप्रेनोर्स बैंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया है हरित ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल की है। कंपनी के प्रमुख दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी पराली से बनाने की दिशा में काम कर रही है। बेमेतरा में इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी में एक उद्भृष्टान्त स्थापित किया गया है, जो जल्द ही पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इस परियोजना का मकसद सिर्फ हरित ईंधन उत्पादन ही नहीं, बल्कि किसानों को पराली बेचने से अतिरिक्त आमदनी देना और प्रदूषण कम करना भी है। कंपनी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ऐसे उद्योगों को तेजी से विकसित किया जा सके।

पर्यावरण अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) उत्पादों के लिए जानी जाने वाली कंपनी डी'एल्लो ड'ए ने छत्तीसगढ़ में अपने उद्योगों के विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी के प्रमुख विमल सिपानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। उत्पाद बनती है, जो पूरी तरह से पर्यावरण

द्वारा लोन स्वीकृत करने के पहले अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है। जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में पिछले करीबन 7-8 वर्ष से कलेक्टर गाइड लाइन के बाजार भाव में जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है और न ही इतने वर्षों में जमीन की कीमत को लेकर कोई सर्वे हुआ है। लंबे समय से कलेक्टर गाइड लाइन में जरूर जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है, लेकिन हकीकत में रायपुर सहित जिले के कई क्षेत्रों में जमीन की कीमत दो से चार गुना तक बढ़ चुकी है। इसे देखते हुए इस बार गाइड लाइन में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना अधिक



है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने मीडिया को बताया कि, नई गाइड लाइन पर काम चल रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसकी जानकारी देगी। पंजीयन विभाग के मुताबिक अचल संपत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका

सिद्धांत वर्ष 2025-26 निर्धारित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों व तहसीलदारों के माध्यम से ली जा रही है। अन्य

जानकारियां जैसे निर्माण लागत, शासकीय व नीलामी विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण के दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित बाजार मूल्य व गाइडलाइन कीमत में न्यूनतम संभावित अंतर हो। रोड से लगकर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल रोड की दर प्रस्तावित की जाएगी। रोड से अंदर की दर प्रस्तावित नहीं की जाएगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। वहीं, किसी रिहायशी कॉलोनी या मोहल्ले में 40 फीट

से अधिक चौड़ाई की सड़क, मुख्य मार्ग मानी जाएगी। नियम के प्रावधानों के अनुसार हर साल की तरह वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति की बाजार मूल्य दरों का पुनरीक्षण किया जाना है। उप जिला मूल्यांकन समिति स्तर पर सभी कार्यवाही 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। वहीं, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव 15 अप्रैल तक प्रस्तुत करने कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले सात वर्षों से जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ी हैं। वर्तमान में वर्ष 2017 की दरें ही लागू हैं। जबकि नियमानुसार कलेक्टर गाइडलाइन दर को हर साल पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान है।

टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़ 3700 करोड़ से अधिक के हुए करार

सीएम विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से किया संवाद

संवाददाता ● रायपुर

छत्तीसगढ़ को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। राज्य में निवेश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इस इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों ने कुल 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस बैठक में कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में अपनी परिचयनाएं शुरू करने को लेकर रुचि दिखाई, जिससे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और द इंडियन एंटरप्रेनोर्स बैंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया है हरित ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल की है। कंपनी के प्रमुख दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी पराली से बनाने की दिशा में काम कर रही है। बेमेतरा में इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी में एक उद्भृष्टान्त स्थापित किया गया है, जो जल्द ही पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इस परियोजना का मकसद सिर्फ हरित ईंधन उत्पादन ही नहीं, बल्कि किसानों को पराली बेचने से अतिरिक्त आमदनी देना और प्रदूषण कम करना भी है। कंपनी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ऐसे उद्योगों को तेजी से विकसित किया जा सके।

पर्यावरण अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) उत्पादों के लिए जानी जाने वाली कंपनी डी'एल्लो ड'ए ने छत्तीसगढ़ में अपने उद्योगों के विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी के प्रमुख विमल सिपानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। उत्पाद बनती है, जो पूरी तरह से पर्यावरण



पराली से बनेगा हरित ईंधन, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर अणु उद्योग ने बड़ी पहल की है। कंपनी के प्रमुख दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी पराली से उद्भृष्टान्त स्थापित किया गया है, जो जल्द ही पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इस परियोजना का मकसद सिर्फ हरित ईंधन उत्पादन ही नहीं, बल्कि किसानों को पराली बेचने से अतिरिक्त आमदनी देना और प्रदूषण कम करना भी है। कंपनी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ऐसे उद्योगों को तेजी से विकसित किया जा सके।

के अनुकूल और प्लास्टिक के बेहतर विकल्प होते हैं। कंपनी ने राज्य में बायोटेक उत्पादों के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार हरित और पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को हरसंभव सहयोग देगी। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और हरित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

टेक्सटाइल उद्योग में बड़े निवेश की संभावना को लेकर के प्रमुख मनोज अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि छत्तीसगढ़ में लेबर और अनुकूल औद्योगिक माहौल की वजह से टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। एमोनो ज अग्रवाल के अनुसार, यदि किसी उद्योग में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद देगी। इस निवेश से न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि राज्य में रोजगार और आर्थिक



वेट्टी कन्नी के साथ 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 26 लाख रुपए का है इनाम

सुकमा। सरकार के नक्सल अभियान को बड़ी सफलता मिली। कोंटा ब्लॉक में नक्सल संगठन में लम्बे समय से सक्रिय वेट्टी कन्नी के साथ 26 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हैसुकमा एसपी किरण चव्हाण, एएसपी उमेश गुप्ता व सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। नक्सली बटालियन में सक्रिय एक नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन और कैप्च खोलने से प्रभावित होकर नौ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें बटालियन नंबर वन के अलावा जयमधुंदा एरिया में शामिल नक्सली हैं। ये नक्सलियों की खोजली विचारधारा को त्यागकर आत्मसमर्पण किया है। इन्हें शासन की आत्मसमर्पण की नीतियों का लाभ दिया जाएगा।

लाखों रुपये खर्च के बाद भी नहीं हुआ स्कूल भवन का निर्माण, शिक्षा के लिए बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को हुए मजबूर, 14 वर्षों बाद भी स्थिति जस की तस

नारायणपुर। आजादी के दशकों बाद भी नारायणपुर जिले के गांव कुण्डोली में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। शासन द्वारा राशि स्वीकृत होने के बावजूद, जिम्मेदार प्रशासन और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते बच्चे अब भी झोपड़ीनुमा घोटला में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है, जहरीले कीड़े-मकोड़ों का खतरा बना रहता है, और बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। जानकारी के मुताबिक शासन ने वर्ष 2022-23 में प्राथमिक शाला भवन के लिए समग्र शिक्षा योजना से 20.30 लाख रुपये और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से 16.10 लाख रुपये,



नारायणपुर। आजादी के दशकों बाद भी नारायणपुर जिले के गांव कुण्डोली में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। शासन द्वारा राशि स्वीकृत होने के बावजूद, जिम्मेदार प्रशासन और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते बच्चे अब भी झोपड़ीनुमा घोटला में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है, जहरीले कीड़े-मकोड़ों का खतरा बना रहता है, और बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। जानकारी के मुताबिक शासन ने वर्ष 2022-23 में प्राथमिक शाला भवन के लिए समग्र शिक्षा योजना से 20.30 लाख रुपये और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से 16.10 लाख रुपये,

कलेक्टर विपिन मांझी को राखी भेजकर आशीर्वाद के रूप में स्कूल भवन और आंगनबाड़ी की मांग की थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

नक्सलियों के डर से नहीं शुरू हुआ काम ?

इलाका नक्सल प्रभावित होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। अधिकारी अक्सर नक्सली गतिविधियों का हवाला देकर काम से बचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो बारिश का बहाना बनाकर इसे और टाल दिया जाएगा।

सीबीआई जांच के खिलाफ कल कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदेशभर में केंद्र और राज्य सरकार का जुलाएंगे पुतला

संवाददाता ● रायपुर

छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के घर सीबीआई की जांच के खिलाफ कांग्रेस कल प्रदेशभर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी। जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि एक के बाद अब उड़क ने महादेव सट्टा एम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में आज दबिशा दी है। भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव और राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर भी उड़क ने छापा मारा है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर ठेक्कपूर्ण करवाई का लगाया है। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने 27 मार्च को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

छत्तीसगढ़ में दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहें सोम्या चौरसिया, विधायक देवेन्द्र यादव, पूर्व क्वर अनिल टुटेजा, क्वर अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, डडर ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व डरकमनी बंधोरे व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापे की खबर है। राजनांदगांव के शक कालोनी सन सिटी में स्थित बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अभिषेक महेश्वरी के घर पर उड़क की टीम पहुंची, जहां उनके घर को सील कर दिया गया है। सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे। भिलाई स्थित आवास में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से टीम पूछताछ कर रही है। वहीं बघेल

केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बीच परिवार के साथ अपने निवास पर मौजूद हैं। वहीं बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव रहें सोम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर सीबीआई की टीम घंटों तक छापेमारी कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर से बरामद किए जाने की चर्चा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी थी। इंडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसका जिम्मा एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंप दिया गया था। इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी द्वारा दायर चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने घोषाघड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसज्जी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे।

प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका को उतारा था मौत के घाट

रायपुर। राजधानी से लगे धरसीवां के मोहदी गांव के खेत में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेमिका का दूसरा प्रेमी होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की थी। आरोपी प्रेमी अरुण निषाद ने अपने साथी समीर निषाद के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर और गले में चाकू से वारकर मौत के घाट उतारा था। हत्या के बाद लाश खेत में फेंककर दोनों फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी थी। लाश के पास मिले आधार कार्ड से मुताका की पहचान नरहादा गांव निवासी संजिता यादव 28 साल के रूप में हुई थी। प्रेमिका की बेवफाई का बदला लेने प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। इधर मुताका के पति ने विधानसभा थाने में पत्नी के गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धरसीवां पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच के बाद हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

भतीजे की हत्या कर झारखंड भागा चाचा, पुलिस ने दबोचा

बिलासपुर। जमीन विवाद के चलते भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी झारखंड में छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे घर दबोचा है। यह मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, कोटा थाने में 10 मार्च को अक्षय कुमार राम ने अपने बेटे सुप्रीम कुमार राम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15 मार्च को ओमकेस कोटा वॉशरी में एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान सुप्रीम कुमार राम, ग्राम डंडई गढ़वा जिला (झारखंड) निवासी के रूप में हुई। कोटा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुप्रीम कुमार राम का अपने चाचा मुकेश कुमार राम से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान पुलिस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्कॉड और साइबर टीम की मदद से अहम सुराग मिले, जिससे आरोपी को लोकेशन झारखंड में होने का पता चला। जानकारी मिलते ही कोटा पुलिस की टीम ने झारखंड पहुंचकर मुकेश कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोटा ले आई। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाई कर रही है।



चेरी ब्लॉसम से महका अमेरिका...

चेरी ब्लॉसम का मौसम टेक्सास में उत्तर के कुछ राज्यों की तुलना में थोड़ा पहले आता है। डलास आर्बोरेटम और बॉटनिकल गार्डन के लगभग 150 पेड़ों का संग्रह आमतौर पर मार्च के मध्य से अंत तक अपने चरम पर होता है। यहाँ के अधिकांश पेड़ सफ़ेद फूल वाले योशिनो चेरी हैं, जो बगीचे के केंद्रीय सैरगाह, पासेओ डे प्लोरेस के साथ लगाए गए हैं।

शॉट न्यूज

पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। इसके लिए कांग्रेस में बिल पेश किया गया है। इस बिल का मकसद पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों पर दमन, खासतौर पर पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सैन्य नेतृत्व की जवाबदेही तय करना है। इस बिल को रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पनेटा ने अमेरिकी संसद में पेश किया है। यह प्रस्ताव 'ग्लोबल मैनिट्रसकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटैबिलिटी एक्ट' के तहत पाक के सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो जनरल मुनीर और अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध के अलावा विदेशों में उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है। इस बिल का डेमोक्रेट सांसद रो ख्वाब इल्हान उमर और रिपब्लिकन सांसद जैक बर्गमैन जैसे 10 सांसदों ने पहले ही समर्थन दे चुके हैं।

यूक्रेन-रूस ब्लैक-सी में सीजफायर पर सहमत

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकने पर सहमत बन गई है। इसके साथ दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का उपाय डेवलप करेंगे। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा- दोनों देश ब्लैक-सी के इलाके में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय करने, बल प्रयोग को रोकने और सैन्य मकसद लिए कॉमर्शियल जहाजों का इस्तेमाल रोकने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका ने इसे लेकर यूक्रेन और रूस से अलग-अलग समझौते किए हैं। सोमवार को अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में 12 घंटे से ज्यादा बैठक हुई थी।

ट्रम्प ने आदेश जारी किया, विदेशी नागरिकों से चंदे पर रोक लगाई

अमेरिका में मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी

एजेंसी • वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को वोट रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। ट्रम्प ने यह आदेश चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए दिया है। ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची में अवेध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के चुनाव में अपनी हार के पीछे फर्जी मतदान को वजह बताया था। हालांकि ट्रम्प के इस आदेश को राज्यों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ट्रम्प ने कल आदेश पर साइन करते हुए कहा- 'चुनावी धोखाधड़ी'। आपने यह शब्द सुना होगा। मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया है कि अमेरिका जरूरी चुनाव सुरक्षा लागू करने में असफल रहा है। इसमें राज्यों को व्हाइट हाउस के साथ सहयोग करने को कहा गया है। अगर कोई राज्य इसमें मदद नहीं करता है तो उन्हें संघ से मिलने वाली फंडिंग रकक सकती है।

आदेश



वोटिंग के लिए राज्यों में नियम अलग-अलग

अमेरिका में वोटिंग को लेकर कोई एकसमान नियम नहीं है। हर राज्य के अपने अलग कानून हैं। टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना जैसे राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया बेहद सख्त है। यहाँ पर वोट डालने के लिए फोटो आईडी (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) दिखाना जरूरी है। वहीं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे राज्यों में वोटिंग को लेकर उतने सख्त नहीं हैं। इन राज्यों में नाम और पता बताकर या फिर कोई दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल दिखाकर वोटिंग की जा सकती है।

विदेशी नागरिकों के चंदा देने पर रोक

इस कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिकी चुनावों में विदेशी नागरिकों द्वारा चंदा देने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। पिछले कुछ सालों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाला चंदा अमेरिकी चुनावों में बड़ा मुद्दा बना है। इसकी एक बड़ी वजह स्विस् अरबपति हैसियोग वीस भी है, जिन्होंने अमेरिका में सैकड़ों मिलियन डॉलर का चंदा दिया है। वीस के समर्थ वाले एक संगठन सिक्सटीन थर्ड फंड ने ओहायो के संविधान में गर्भपात सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। हाल ही में, कंसस ने भी इसी तरह का एक विधेयक पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों द्वारा राज्य के संवैधानिक संशोधनों के पक्ष या विरोध में अभियान चलाने के लिए चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जंग से परेशान गाजावासियों का टूटा सब्र, हमस के खिलाफ सड़कों पर उतरे

एजेंसी • गाजा

गाजा पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से जंग की आग में जल रहा है। इस साल जनवरी में हुए संघर्षविराम समझौते के बाद गाजावासियों के मन में जो आस जगी थी वह भी अब धुंधली पड़ रही है। इस जंग में अब तक 50 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और फिलहाल इजरायल ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच हमस के लोगों का सब्र जवाब देने के लिए कम हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में अधिकांश पुरुष प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। बेत लाहिया में 'हमास बाहर जाओ' और 'हमास आतंकवादी' जैसे नारे लगाए गए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले लोगों ने इस जंग के खत्म ना होने का एक कारण हमस को भी बताया है। लोगों ने कहा है कि वे थक चुके हैं और अब युद्ध का समाधान चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले एक शख्स ने बताया, 'मैंने लोगों की ओर से एक संदेश भेजने के लिए इसमें भाग लिया। बहुत हो गया युद्ध' उन्होंने बताया कि इस



दौरान हमस के लड़ाकों ने इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश भी की। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि लोग थक चुके हैं। उन्होंने कहा, 'अगर गाजा में हमस का सत्ता छोड़ना समाधान है तो हमस लोगों बचाने के लिए सत्ता क्यों नहीं छोड़ता? गौरतलब है कि इजरायल लंबे समय से गाजा के लोगों से इस्लामवादी आंदोलन के खिलाफ इकट्ठा होने की अपील करता रहा है। इस क्षेत्र में 2007 से बड़े पैमाने पर हमस का ही नियंत्रण है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गाजा के लोग हमस के नियंत्रण से खुश हैं या नहीं। सितंबर में फिलिस्तीनी नीति और सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र (PCPSR) की एक रिसर्च के मुताबिक गाजा में 35 प्रतिशत फिलिस्तीनियों ने कहा कि वे हमस का समर्थन करते हैं।

जापान सरकार देगी 12 करोड़ मुआवजा

बॉस की हत्या के आरोप, जेल में बिताए 47 साल

एजेंसी • टोक्यो

जापान की सरकार ने 89 साल के इवाओ हाकामाता को हत्या के झूठे आरोप में 47 साल जेल में रहने के बदले 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। हाकामाता को 1968 में गिरफ्तार किया गया था। वह 2014 तक सजा काट रहे थे। पिछले साल सितम्बर में जापान के शिजुओका शहर की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन्हें 1966 में अपने बॉस, उसकी पत्नी और उनके दो बच्चों की हत्या, घर में आग लगाने और 200,000 येन (जापानी करेंसी) चुराने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। हाकामाता के वकीलों के मुताबिक यह देश के इतिहास में किसी भी क्रिमिनल केस में दिया गया सबसे बड़ा मुआवजा है। हाकामाता की बहन हिदेको ने अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कई सालों तक मेहनत करके सबूत जुटाए। जिसके बाद कोर्ट ने 2014 में इस केस की फिर से सुनवाई शुरू की और हाकामाता को जेल से रिहा कर दिया। हिदेको ने कहा कि मैं इस दिन का 57 साल से इंतजार कर रही थी और वह दिन आ गया। आखिरकार मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया। ज्यादा उम्र और बिगड़ती मानसिक स्थिति की वजह से उन्हें केस की सुनवाई में शामिल होने से छूट दी गई थी। वह अपनी 91 साल की बहन हिदेको की देखरेख में रह रहे थे।

मुआवजा

डीएनए से हाकामाता के डीएनए मेल नहीं खाया



हाकामाता की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा

यह मामला जापान के सबसे लंबे और सबसे प्रसिद्ध कानूनी मामलों में से एक है। उनके वकीलों का कहना था कि वे दुनिया में सबसे

गिरफ्तारी के बाद हाकामाता ने शुरू में तो सभी आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में आरोपों को स्वीकार कर लिया था। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि हाकामाता की पिटाई करके उनसे जब्त कबूलनामा लिया गया था। उनके वकीलों ने कहा कि पीड़ितों के कपड़ों से मिला डीएनए और हाकामाता का डीएनए मेल नहीं खाता है। आरोप लगाने के लिए झूठे सबूत गढ़े गए थे।

लंबे वक्त तक मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदी बन गए हैं। इस सजा ने उनके मानसिक हेल्थ पर बुरा असर डाला।